P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-10* June- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

स्वच्छ विश्व के लिए समग्र सोच

मंजय कुमार
वरिष्ठ प्रवक्ता,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
आई0 एम0 आर0,
दुहाई, गाजियाबाद

सारांश

हाल ही में जर्मनी के बॉन शहर में पर्यावरण व जलवायु के मुद्दों पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का नारा था– फरदर, फास्टर एंड टुगेदर यानि एकजुट होकर तेजी से आगे बढ़ना। इस तीनों मकसद में सम्मेलन नाकाम रहा। काफी कवायद के बाद सम्मेलन का निचोड़ निकालने वाली संयुक्त कमेटी ने जो स्टेटमेंट जारी किया उससे यही जाहिर होता है। कमेटी ने रणनीतिक मुद्दों पर कुछ बिन्दु जारी किये जिस पर अगले साल पोलैंड में होने वाले जलवायु सम्मेलन (सीओपी 24) में चर्चा होगी और सम्भवतः जब किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 विकसित व विकासशील देशों के अफसरों और राजनीतिज्ञों के लिए पर्यटन और मौजमस्ती से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉन के संयुक्त राष्ट्र कैम्पस से दुनिया भर से आये करीब पच्चीस हजार प्रतिनिधियों के आपसी संवाद के लिए एक पाँच सितारा सुविधाओं वाला अस्थायी शहर बसाया गया था। बाहर का तापमान भले ही 3 डिग्री सेल्सियस हो लेकिन इस परिसर में भीतर के तापमान को गर्म रखने के लिए लाखों वाट की लाइटें व हीटर लगाये गये। अप्राकृतिक तौर से पैदा की जा रही गर्मी जलवायु परिवर्तन के लिए कितनी जिम्मेदार है इसका आंकलन किसी के पास नहीं है।

दावे चाहे कितने भी किये जायें, संविधानों और कानूनों में चाहे जितने प्रावधान किये जायें, धरती के रक्षार्थ हेतु स्वच्छ विश्व की स्थापना के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कितने ही लच्छेदार भाषण क्यों न दिये जायें, लेकिन अभी भी स्वच्छ विश्व का सपना अधूरा है, इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.....।

मुख्य शब्द : ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनलैंड, पर्यावरण, दोहन, जलवायु परिवर्तन।

प्रस्तावना

दो दशक से भी पहले से वायु प्रदूषण नियन्त्रण के औपचारिक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी दौरान विभिन्न तरह के फैसले लिए गये, जिनमें जीवाशम ईंधन के विभिन्न स्रोतों, जैसे उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों और वाहनों आदि से निपटने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि उसके बाद वाहनों की संख्या में वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन से कमी, शहरों में और उसके आसपास औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और अन्य कारणों के समय निर्माण गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला गया।

आज जैसे–जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इसके परिणामस्वरूप होने वाली समस्यायें, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि का प्रभाव बड़ा ही हानिकारक होता जा रहा है।

यदि आप अखबारों के पन्ने उलटे या खबरिया टीवी चैनल देखें तो आपको एहसास होगा कि जीवन और मृत्यु से जुड़े इस मुद्दे से निपटने में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कितनी कमी है। इस प्रदूषण से प्रभावित सभी देश एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।

ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का विषय शिक्षित समाज पर्यावरणवादियों, वैज्ञानिकों, मीडिया कर्मियों और कतिपय जनप्रतिनिधियों के बीच धीरे–2 चर्चा का मुद्दा बन रहा है। इस विषय की चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन की संभावनाओं के मद्देनजर उसके मानव सभ्यता एवं समस्त जीवधारियों पर संभावित प्रभाव की भी चर्चा होने लगी है। पर्यावरणविदों एवं कतिपय वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि समय रहते ही ठोस कदम नहीं उठाये तो अनेक जीवधारियों के जीवन पर असर पड़ेगा और कुछ जीवजन्तुओं का नामोनिशान मिट जायेगा।

कारण

वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन का कारण माना जाता है। वातावरण की मुख्य ग्रीन हाउस में से पानी की भाप, कार्बनडाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन मुख्य हैं। अवलोकनों से पता चला है कि वातावरण में कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। इंटरगवमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) के अनुसार ग्रीनहाऊस गैसों के प्रभावों से समुद्र का पानी धीरे–धीरे अम्लीय हो रहा है और मौसमी दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता को समझने के लिए बर्फ के सबसे बड़े भंडारों की परिस्थितियों को देखना और समझना होगा। दुनिया में बर्फ के सबसे बड़े भंडार अन्टार्कटिका और ग्रीनलैंड में है। इनका पर्यावरण ही दुनिया की जलवायु परिवर्तन का सूचक है। आंकड़े बताते हैं कि हाल के सालों में ग्रीनलैंड का औसत तापमान 5 डिग्री बढ़ा है। पिछले 10 सालों में बर्फ की चादर के टूटकर समुद्र में गिरने की घटनाओं में 75 प्रतिशत की तेजी आयी है। इसके कारण अगले कुछ वर्षों में द्वीप समूहों की कोरल–रीफ के 80 से 100 प्रतिशत तक लुप्त होने का खतरा रहेगा। साथ ही परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में मछलियों की पैदावार कम हो चुकी है। प्राचार्य आई0ए0एम0आर0 कॉलेज, पाँचली, मेरठ।

दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का असर होगा। अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आयेगी। इसके अलावा समुद्र के जलस्तर में बदलाव के कारण लगभग 10 करोड़ लोगों का विस्थापन होगा। सूखे के इलाकों में पाँच गुना वृद्धि होगी लाखों लोग सूखे के कारण शरणार्थी बनेगे। हर छटवाँ व्यक्ति जल कष्ट से पीड़ित होगा। अनुमान है कि लगभग 40 प्रतिशत प्रजातियां हमेशा–हमेशा के लिए धरती पर से लुप्त हो जायेंगी।

पर्यावरण स्वच्छ बनाने के उपाय

पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों की फ्यूल–दक्षता बढ़ानी होगी। वाहनों में बायोडीजल और एथीनाल का अधिकाधिक उपयोग करना होगा। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। इसी तरह वाहनों में सोलर बैटरी का उपयोग बढ़ाना होगा और बिजली बनाने में विन्ड एनर्जी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। पूरी दुनिया को बिना कार्बन के ऊर्जा पैदा करने वाली अर्थनीति अपनानी होगी और अमीर देशों द्वारा ग्रीनहाऊस गैसो के उत्सर्जन में कमी करना होगा तथा गरीब देशों को विकास के लिए ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में छूट देना होगा। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकरण और मानवीय हस्तक्षेप जुड़ गये हैं। यह तो कहना कठिन है पर यह तय है कि भाग्यशाली प्रजातियां ही धरती पर राज करेंगी।

सर्वाधिक गैस उत्सर्जन के लिए बदनाम अमेरिका ने, पेरिस समझौते से बाहर होने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा ही बेतुका बयान दिया है कि मैं अमेरिका के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये हैं न कि पेरिस संधि के प्रतिनिधित्व के लिए। अमेरिका के इस रुख का पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी एक्टबिस्ट भी मुखर विरोध कर रहे हैं। न्यूयार्क के पूर्व मेयर व जलवायु सुंरक्षण पर लाखों डॉलर खर्च कर चुके एक्टविस्ट माइकल व ब्लूमबर्ग ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोयले को प्रमोट करना वैसा ही है जैसे कैंसर सम्मेलन में तम्बाकू का प्रचार करना। ये तकलीफदेह है। ब्लूमबर्ग ने इसी हफ्ते जलवायु संरक्षण के लिए 50 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है।

COP - 23 बॉन (जर्मनी) 2017 का विशेष परिचय

हाल ही में जर्मनी के बॉन शहर में पर्यावरण व जलवायु के मुद्दों पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का नारा था– फरदर, फास्टर एंड टुगेदर यानि एकजुट होकर तेजी से आगे बढ़ना। इस तीनों मकसद में सम्मेलन नाकाम रहा। काफी कवायद के बाद सम्मेलन का निचोड़ निकालने वाली संयुक्त कमेटी ने जो स्टेटमेंट जारी किया उससे यही जाहिर होता है। कमेटी ने रणनीतिक मुद्दों पर कुछ बिन्दु जारी किये जिस पर अगले साल पोलैंड में होने वाले जलवायु सम्मेलन (सीओपी 24) में चर्चा होगी और सम्भवतः जब किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 विकसित व विकासशील देशों के अफसरों और राजनीतिज्ञों के लिए पर्यटन और मौजमस्ती से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉन के संयुक्त राष्ट्र कैम्पस से दुनिया भर से आये करीब पच्चीस हजार प्रतिनिधियों के आपसी संवाद के लिए एक पाँच सितारा सुविधाओं वाला अस्थायी शहर बसाया गया था। बाहर का तापमान भले ही 3 डिग्री सेल्सियस हो लेकिन इस परिसर में भीतर के तापमान को गर्म रखने के लिए लाखों वाट की लाइटें व हीटर लगाये गये। अप्राकृतिक तौर से पैदा की जा रही गर्मी जलवायु परिवर्तन के लिए कितनी जिम्मेदार है इसका आंकलन किसी के पास नहीं है।

पर्यावरण के सम्मेलन तभी सफल हो सकेंगे, जब विकास का अर्थ ऐसी व्यवस्था बढ़ाना होगा, जिसमें उद्योग प्रकृति का दोहन न करे।

जलवायु परिवर्तन के प्रयास को रोकने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि दुनिया को गरम होने से बचाने का मुद्दा दरअसल उद्योगों से जुड़ा हुआ है। अगर हम 'ग्लोबल वार्मिंग' को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने उद्योगों का मिजाज बदलना होगा। मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है– न उद्योग और न सरकारें।

दुनिया के 20 सबसे बड़े देश, जिन्हें विकसित देशों का दर्जा प्राप्त है, अकेले 96 हजार अरब डॉलर उद्योगों से जुटाते हैं। यह आंकड़ा आईएमएफ के 2016 के सर्वेक्षण के अनुसार है। इनमें से ज्यादा कमाई चीन की है, जो लगभग 4,566 अरब डॉलर है। दूसरे और तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ व अमेरिका हैं, जिनकी कमाई क्रमशः 4, 184 और 3,602 अरब डॉलर है। इन देशों में

सबसे कम कमाई पोलैंड की है, जिसकी उद्योगों से आय 180 अरब डॉलर है। भारत की आय 672 अबर डॉलर के आस–पास है, जो ब्रिटेन और फ्रांस से ज्यादा है।

आय के ये आंकड़े दरअसल प्रदूषण में हिस्सेदारी के आंकड़े भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन डाई–ऑक्साइड का उत्सर्जन है। चीन, जिसका आर्थिक प्रगति में पहला स्थान है, उसका कार्बन उत्सर्जन में भी सबसे ज्यादा योगदान है। विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 30 फीसदी अकेले चीन उत्सर्जित करता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसका 2013 में कार्बन उत्सर्जन 5.8 अरब टन था। इसके मुकाबले भारत से होन वाला सालाना कार्बन डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन 6 अरब टन है। इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की जीडीपी में उद्योगों की भागीदारी 19.1 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह लगभग 40 प्रतिशत है। भारत में उद्योग 26 प्रतिशत का योगदान करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में तो यह आंकड़ा 60 प्रतिशत से ऊपर है। दूसरी तरफ, सभी देशों में खेती–बाड़ी में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिका की जीडीपी में कृषि की भागीदारी 1.12 प्रतिशत है। जापान, ब्रिटेन और कनाड़ा में भी ऐसे ही हालात हैं। यहां जीडीपी में खेती की भागीदारी दो प्रतिशत से भी कम है। भारत में यह हिस्सेदारी लगभग 17 फीसदी है, जो स्वतंत्रता के समय 40 प्रतिशत की आसपास थी। इसी तरह चीन में 2010 में खेती की भागीदारी 10.2 प्रतिशत थी, जिसमें 2016 आते–आते दो फीसदी की ओर गिरावट आ गई। आज दुनिया में भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीनिया, इराक, थाइलैंड जैसे कुछ गिने–चुने देश ही हें जिनकी जीडीपी में खेती की भागीदारी 10 प्रतिशत से ऊपर है।

जाहिर है, अर्थव्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उद्योगों के सिर पर ही है। दिक्कत यह भी है कि इसमें वे उद्योग बहुत आगे हैं, जो अपने उत्पाद या अपनी योगदान प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक संसाधनों, खासकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। कई देश ऐसे हैं, जिनकी जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी खनिज तेल के व्यापार की है। कांगो, कुवैत, इराक, इरान, सऊदी अरब इन सब की जीडीपी में तेल की भागीदारी 60 प्रतिशत से ऊपर है। दुनिया में गिने–चुने ही देश हैं, जिन्हें संतुलित कहा जा सकता है। खेती व उद्योगों पर अर्थव्यवस्था समान रूप से निर्भर है, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जो उनका दोहन कर रहे हैं या उनकी कीमत पर उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वे अगड़े हैं।

दिक्कत यह है कि बॉन के पर्यावरण सम्मेलन में यह मसला इस तरह से नहीं उठाया जाएगा, सम्मेलन में व्यक्त की जाने वाली सारी चिंताएं बेमतलब रहेंगी। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि पर्यावरण के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी है, वह दरअसल आर्थिक लड़ाई भी है। इसे स्वीकार न कर पाने के कारण ही अक्सर ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन झगड़ों में बदल जाते हैं, या फिर एक–दूसरे पर आरोप लगाने में। पिछड़े दिनों अमेरिका ने पेरिस समझौते से हाथ खींच लिए थे। उनका कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए उठाए गए कदमों से उसे नुकसान होगा और भारत जैसे देशों को लाभ। यहां नुकसान का मतलब अमेरिका के उद्योगों के नुकसान से है, वरना इससे अमेरिकी सरकार या जनता का कोई सीधा नुकसान नहीं होने जा रहा है।

निष्कर्ष

पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का मसला दरअसल उद्योगों को रोकने या पुरानी कृषि व्यवस्था की ओर लौटने का नहीं है। लौटना तो शायद कभी संभव नहीं होता। यह मसला विकास और विज्ञान की सोच बदलने का है। हमें वह रास्ता अपनाना ही होगा, जिससे विकास का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न रहे। उद्योग ऐसे हों, जो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने की बजाय उन्हें रोकें। समाज और अर्थव्यवस्था को इस ओर ले जाने के लिए अब विज्ञान को सक्रिय होना होगा। शुरु में हो सकता है कि इससे उद्योगों को कोई नुकसान भी हो लेकिन अंत में इससे सबको फायदा मिलेगा। हमें पर्यावरण पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को इसी ओर ले जाना होगा। जब तक यह नहीं होता, पर्यावरण पर होने वाले कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न तो सफल होगा और इससे कोई सर्वमान्य संधि ही निकल सकेगी। सम्मेलन या उद्योग को बचाने से ज्यादा बड़ा समय धरती को बचाने का है।

दावे चाहे कितने भी किये जायें, संविधानों और कानूनों में चाहे जितने प्रावधान किये जायें, धरती के रक्षार्थ हेतु स्वच्छ विश्व की स्थापना के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कितने ही लच्छेदार भाषण क्यों न दिये जायें, लेकिन अभी भी स्वच्छ विश्व का सपना अधूरा है, इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.....।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *हिन्दुस्तान, कानपुर 13 नवम्बर 2017।*
2. *भट्नागर, शेखर 2017, पर्यावरण शिक्षा लाल बुक डिपो, मेरठ।*
3. *प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2017, आगरा।*
4. *शर्मा, राकेश, पर्यावरण शिक्षा के नये आयाम।*
5. *उजाला मेरठ 5 नवम्बर 2017।*